



## निदेशकों की रिपोर्ट

### प्रबंधन विवेचन और विश्लेषण

#### आर्थिक पृष्ठभूमि और बैंकिंग परिवेश

भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान है। दुनिया भर में वित्तीय संकट और आर्थिक गतिविधियों के धीमी रहने के बावजूद यह अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। भारत वैश्विक वित्तीय हलचल के दौर में भी अडिग खड़ा रहा। ऐसा ठोस विनियमन व्यवस्था, विवेकपूर्ण वित्तीय पर्यवेक्षण और सुनिर्धारित नीतियों के कारण संभव हुआ।

भारत की विकास दर मुख्यतया घरेलू खपत और निवेश पर निर्भर है। भारतीय बैंकों द्वारा न तो यू एस ए की सब प्राइम मार्टगेज आस्तियों में और न ही दिवालिया हुई संस्थाओं में कोई सीधा निवेश किया गया है। इसलिए जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है, भारत विश्व के सर्वाधिक तेज गति से बढ़ रहे देशों में अग्रणी बना रहेगा। वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति की ऊँची दर और कच्चे तेल की घटती-बढ़ती कीमतें चिंता का प्रमुख कारण रहीं किंतु दूसरी छमाही में निरंतर विकास और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया।

जीडीपी वृद्धि-दर वर्ष 2007-08 के 9.0% के स्तर से घटकर वर्ष 2008-09 में 6.5% से 6.7% के बीच रहने की संभावना है। वर्ष 2008-09 में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की वृद्धि-दर के लगभग 2.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्ष 2000-01 से 2007-08 की औसत वृद्धि-दर 2.9% की तुलना में मामूली सी कम है। इस कमी का मुख्य कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट है।

औद्योगिक उत्पादन पर विनिर्माण क्षेत्र की धीमी गति का प्रभाव दिखाई दिया। वर्ष 2008-09 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2.4% के स्तर पर आ गया जो वर्ष 2007-08 में 8.5% पर था। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट के कारण उद्योगों की गति धीमी रही। हालांकि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सुधार के कारण वर्ष 2008-09 के दौरान कुल उत्पादन में 4.4% की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2007-08 में 1.0% की कमी आई थी। इसके बावजूद खपत और निवेश में अनुमान के अनुसार वृद्धि हुई।

उद्योग और कृषि क्षेत्र के धीमा होने की वर्ष 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) में सेवा क्षेत्र की 9.7% की संतुलित वृद्धि-दर से कुछ भरपाई हुई। सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं की वर्ष 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) में वृद्धि-दर 11.2% के उच्च स्तर पर रही जबकि वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसंबर) में यह 5.7% रही थी। वर्तमान धीमी गति के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की गई। इनमें अप्रत्यक्ष करों में रियायतें देने, सरकारी खर्च में वृद्धि करने और निर्यातों के लिए सहायता देने के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत अनेक प्रकार की सुविधाएँ भी दी गईं।

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर मार्च 2008 के अंत में 7.7% थी, जो 2 अगस्त 2008 को 12.9% के उच्च स्तर पर पहुँच गई। ऐसा कच्चे तेल और पण्यों के साथ साथ विनिर्मित उत्पादों तथा मूलभूत वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊँची कीमतों के कारण हुआ। जून और अक्टूबर 2008 के दौरान 10-12% के बीच बने रहने के बाद नवंबर 2008 से मुद्रास्फीति कम होते होते 28 मार्च 2009 को 0.26% के स्तर पर आ गई। ऐसा मुख्यतया कच्चे तेल, धातुओं और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आने के कारण हुआ।

विश्व स्तर पर आर्थिक विकास की दर कम होने से भारतीय सामान और सेवाओं की विदेश में मांग कम हुई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई और प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य कम हुआ। निर्यातों में कमी अक्टूबर 2008 से शुरू हुई और तब से हर महीने निर्यात की वृद्धि-दर नकारात्मक बनी हुई है और सबसे बड़ी 33.3% की गिरावट मार्च 2009 में देखी गई। इसी कारण वर्ष 2008-09 के दौरान निर्यातों की वृद्धि-दर वर्ष 2007-08 के 28.9% के स्तर से गिरकर 3.4% पर आ गई। आयातों में भी वर्ष 2008-09 में वृद्धि-दर 14.3% दर्ज की गई, जो वर्ष 2007-08 की 35.4% की तुलना में काफी कम है। ऐसा कच्चे तेल की कीमतों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से गिरने के कारण हुआ। वैश्विक वित्त बाजारों में व्याप्त जोखिम के चलते उनसे विमुखता के कारण भारत में पूंजी की आवक पर भी तेजी से विपरीत असर हुआ। इस कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा वर्ष 2008-09 में भारत से लगभग 15.0 बिलियन



## Directors' Report

### *Management Discussion and Analysis*

#### **Economic Backdrop and Banking Environment**

The Indian economy, which is one of the fastest growing economies in the world, is poised to maintain its leading position, despite the global financial crisis and economic slowdown. India has managed to beat the global financial turmoil due to sound regulation, prudent financial supervision and proactive policies.

India's growth is driven predominantly by domestic consumption and investment and the Indian banking system has no direct exposure to the US sub-prime mortgage assets or to the failed institutions. Thus, as also projected by the IMF, India will remain among the fastest growing economies in the world. In the first half of the year, high inflation and spiralling crude oil prices were the major concerns, but the focus in the second half shifted to sustaining growth and maintaining stability.

Real GDP growth is expected to moderate from 9.0% in 2007-08 to 6.5% - 6.7% in 2008-09. Agriculture and allied sectors are likely to grow by around 2.6% in 2008-09, which is only marginally lower than the average growth of 2.9% during 2000-01 to 2007-08, mainly due to stagnant foodgrains production.

Industrial production was marked by a slowdown in the manufacturing sector. During 2008-09 the Index of Industrial Production decelerated to 2.4% against 8.5% in 2007-08. The deceleration in capital goods reflects the slowdown in industry. The rebound in consumer durables during 2008-09 at 4.4% against decline of 1.0% in 2007-08, however, reflects a measured pick up in consumption and investment.

The slowdown in industry and agriculture was partially offset by a reasonable 9.7% growth in services sector in 2008-09 (April-Dec) with

community, social and personal services showing a higher growth of 11.2% in 2008-09 (April-Dec) than the 5.7% growth posted in 2007-08 (April-Dec). To mitigate the impact of the current slowdown, Government launched three fiscal stimulus packages in the form of cut in indirect taxes, higher Government spending and support for exports, along with easing of monetary policy by RBI.

Inflation based on WPI rose from 7.7% at end-March 2008 to a high of 12.9% on 2nd August 2008, reflecting high international crude oil and commodity prices coupled with increase in price of manufactured products and primary articles. After remaining in the range of 10-12% between June and October 2008, inflation began to ease from November 2008 onwards to touch 0.26% by 28th March 2009, mainly reflecting the decline in prices of crude oil, metals, minerals and manufactured goods.

The deceleration in economic growth globally was reflected in weakness in external demand for goods and services, besides decline in forex reserves and depreciation of the rupee against major currencies. The fall in exports began in October 2008 and every month since then, export growth has been negative with the biggest decline of 33.3% in March 2009. Consequently, growth in exports during 2008-09 was lower at 3.4% than 28.9% in 2007-08. Imports also registered a lower growth of 14.3% in 2008-09 as against 35.4% in 2007-08, mainly due to fall in international crude oil prices. The risk aversion in the global financial markets resulted in a sharp reversal in capital inflows into India, with net outflow by foreign institutional investors (FIIs) of around US\$15.0bn in 2008-09 compared with an inflow of US\$20.3bn in 2007-08. As a result of decline in exports and capital outflows from the domestic stock market, forex reserves fell by US\$57.70 bn YoY to US\$252.00 bn as at end-



यू एस डॉलर की निवल पूंजी निकाल ली गई, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2007-08 में 20.3 बिलियन यू एस डॉलर की पूंजी भारत में आई थी। निर्यातों में कमी आने और देश के शोयर बाजारों से पूंजी के बाहर जाने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वर्षानुवर्ष 57.70 बिलियन अमरीकी डॉलर की गिरावट के साथ यह मार्च 2009 के अंत में 252.00 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया। वर्ष 2009 के अंत में रुपये का मूल्य कम होकर रु. 50.95 प्रति डालर के स्तर पर आ गया जबकि मार्च 2008 के अंत में यह रु.39.99 प्रति डॉलर के स्तर पर था।

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक की मुद्रा और ऋण नीति मुद्रास्फीति नियंत्रण, वित्त बाजार स्थायित्व बनाए रखने, वित्त व्यवस्था में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही ताकि ऋण की मांग की पूर्ति और इस पर वर्तमान वैश्विक संकट के प्रभाव को सीमित रखा जा सके। वर्ष 2008-09 के दौरान 6% बैंक दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि रिवर्स रेपो विशेषकर रेपो दर और सीआरआर में अनेक अवसरों पर परिवर्तन किया गया। जब पण्यों और तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की दर में बढ़ोतरी शुरू हुई तो रेपो दर को अप्रैल 2008 के 7.75% के स्तर से बढ़ाकर जुलाई 2008 में 9% और सीआरआर को मार्च 2008 के 7.50% के स्तर से बढ़ाकर अगस्त 2008 में 9% किया गया। बाद में जब वृद्धि-दर थम गई और कच्चे तेल और पण्यों की कीमतों में कमी होने के कारण मुद्रास्फीति की दर गिरनी शुरू हुई तो अक्टूबर 2008 और मार्च 2009 के बीच रेपो दर 5 बार कटौती करके 5% पर रिवर्स रेपो दर 3 बार कटौती करके 3.50% पर और सीआरआर 4 बार कटौती करके 5.0% पर लाई गई। बैंकों की जमा और उधार दरें कमोबेश मुद्रा और ऋण नीति में घोषित प्रमुख दरों के अनुरूप घटती-बढ़ती रहीं। ब्याज दरों में वर्ष 2008-09 के दौरान प्रारंभ में अक्टूबर 2008 तक वृद्धि हुई और बाद में नवंबर 2008 के पश्चात कमी आनी शुरू हुई। पूंजी के बाहर जाने और आर्थिक गतिविधियों के धीमी होने का यह प्रभाव हुआ कि वर्ष की दूसरी छमाही में वित्त व्यवस्था में स्थूल मुद्रा (एम 3) की वृद्धि-दर मामूली सी कम रही और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यवसाय में थोड़ी कमी आई। तथापि स्थूल मुद्रा (एम 3) एक वर्ष पहले 21.1% थी जो 2008-09 में थोड़ी कम होकर 18.6% के स्तर पर आ गई। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और ऋण

वृद्धि-दर वर्ष 2007-08 के क्रमशः 22.4% और 22.3% के स्तर से कम होकर 19.8% और 17.3% पर आ गई।

आगामी वर्ष में भी अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि वैश्विक संकट का प्रभाव अनुमान से कहीं अधिक गहरा एवं व्यापक होने की संभावना है। फिर भी, एक स्थिर बैंकिंग और वित्त क्षेत्र, मुद्रास्फीति की गिरती दर और शीघ्रता से किए गए समन्वित नीतिगत उपायों की सहायता से भारत इस संकट का सामना करने में सफल रहा। उत्साहवर्धक बात यह है कि देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ने से और सरकार द्वारा निवेश गतिविधियों को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में योगदान करने की संभावना को देखते हुए भारत के विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पर रहने की उम्मीद है।

### वित्तीय निष्पादन

#### लाभ

वर्ष 2007-08 के रु. 13,107.55 करोड़ की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक का परिचालन लाभ रु. 17,915.23 करोड़ रहा और इस प्रकार इसमें 36.68% की वृद्धि हुई। वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक का निवल लाभ 35.55% की दर से बढ़कर वर्ष 2007-08 के रु. 6,729.12 करोड़ की तुलना में रु. 9,121.23 करोड़ हो गया।

निवल ब्याज आय में 22.63% की वृद्धि हुई और अन्य आय में 45.96% की वृद्धि हुई। उच्चतर स्टाफ लागत और अन्य उपरि व्ययों के कारण परिचालन व्ययों में 24.11% की बढ़ोतरी हुई।

#### लाभांश

बैंक ने लाभांश पिछले वर्ष के रु. 21.50 प्रति शोयर (215%) से बढ़ाकर रु. 29.00 प्रति शोयर (290%) कर दिया।

#### निवल ब्याज आय

बैंक की निवल ब्याज आय में 22.63% की वृद्धि हुई और यह 2007-08 के रु. 17,021.23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 20,873.14 करोड़ हो गई। यह अग्रिमों पर ब्याज-आय में वृद्धि का परिणाम था।

वैश्विक परिचालनों से वर्ष के दौरान सकल ब्याज आय रु. 48,950.31 करोड़ से बढ़कर रु. 63,789.43 करोड़ हो गई। ऐसा मुख्यतया अग्रिमों से उच्च ब्याज आय होने के कारण हुआ।



March 2009. The Rupee depreciated to Rs.50.95 per dollar at end-March 2009 from Rs.39.99 per dollar at end-March 2008.

The focus of RBI's monetary and credit policy during the year was to control inflation, support growth, maintain financial market stability, ensure comfortable liquidity in the system to meet the required credit demand and limit the contagion from the ongoing global turmoil. During 2008-09, while the Bank Rate was kept unchanged at 6%, Reverse Repo and more particularly the Repo rate and CRR were changed on a number of occasions. When inflation started rising due to increase in international commodity and oil prices, the Repo rate was hiked from 7.75% in April 2008 to a high of 9% in July 2008 and CRR was hiked from 7.50% in March 2008 to 9% in August 2008. Subsequently, when growth stalled and inflation started coming down due to drop in crude oil and commodity prices, the Repo rate was cut five times to 5%, the Reverse Repo rate was reduced three times to 3.50% and CRR was cut four times to 5.0%, between October 2008 and March 2009.

Deposit and lending rates of banks also moved more or less in tandem with key policy rates as interest rates initially firmed up during 2008-09 up to October 2008, and subsequently started declining after November 2008. The capital outflows and slowdown in economic activity, particularly in the second half of the year, impacted money supply growth in the system (M3) and saw moderation in the business of all scheduled commercial banks (ASCB). While growth in money supply (M3) moderated to 18.6% in 2008-09 from 21.1% a year ago, deposit and credit growth of ASCB moderated to 19.8% and 17.3% respectively in 2008-09 from 22.4% and 22.3% in 2007-08.

The coming year will continue to be marked with uncertainty as the impact of the global crisis has been deeper and wider than earlier anticipated. However, a stable banking and financial sector, falling inflation and prompt co-ordinated policy

action have helped India weather the crisis. On the upside, domestic demand especially from rural areas, and Government investment activity in the economy will help keep up the growth momentum, making India the second fastest growing economy in the world.

## *Financial Performance*

### **Profit**

The Operating Profit of the Bank for 2008-09 stood at Rs. 17,915.23 crores as compared to Rs. 13,107.55 crores in 2007-08 registering a growth of 36.68%. The Bank has posted a Net Profit of Rs. 9,121.23 crores for 2008-09 as compared to Rs. 6,729.12 crores in 2007-08 registering a growth of 35.55%.

While Net Interest Income recorded a growth of 22.63% and Other Income increased by 45.96%, Operating Expenses increased by 24.11% attributable to higher staff cost and other overhead expenses.

### **Dividend**

The Bank has increased dividend to Rs. 29.00 per share (290%) from Rs. 21.50 per share (215%) in the last year.

### **Net Interest Income**

The Net Interest Income of the Bank registered a growth of 22.63% from Rs. 17,021.23 crores in 2007-08 to Rs. 20,873.14 crores in 2008-09. This was due to growth in interest income on advances.

The gross interest income from global operations rose from Rs. 48,950.31 crores to Rs. 63,788.43 crores during the year. This was mainly due to higher interest income on advances.

Interest income on advances in India registered an increase from Rs. 32,162.68 crores in 2007-08 to Rs. 42,989.36 crores in 2008-09 due to higher volumes. Also average yield on advances in India increased from 9.90% in 2007-08 to 10.15% in 2008-09. Interest income on advances at foreign offices also increased due to higher volumes.